NO PASSWORD SHARING FOR NETFLIX

Netflix has ended password sharing in India and other markets like Kenya, Indonesia and Croatia after testing it out in countries like US and Canada.

"We will be sending this email to members who are sharing Netflix outside their household in India. A Netflix account is for use by one household. Everyone living in that household can use Netflix wherever they are at home, on the go, on holiday and take advantage of new features like Transfer Profile and Manage Access and Devices. We recognise that our members have many entertainment choices. It is why we continue to invest heavily in a wide variety of new films and TV shows so whatever your taste, mood or language and whoever you are watching with, there is always something satisfying to watch on Netflix," said the company.

According to Netflix's financial report for Q2 for 2023, it has gained 5.89 million subscribers in Q2, taking the total number of global streaming paid subscribers to 238.39 million. In Q1, Netflix had added 1.75 million paid subscribers.

COURT RELIEF FOR DISNEY+ HOTSTAR

The Madras High Court has granted interim relief to Star India's subsidiary Novi Digital Entertainment after it filed a plea against Google Play Store's new billing system, media reports said. Novi Digital is the owner of Disney+ Hotstar.

The court has restrained Google from delisting Disney+ Hotstar from the app store.

Novi Digital has been told to pay 4% commission on Play Store downloads. The company has told the court that as per the new billing policy app developers have to pay 11% fee to Google Pay even if they opt for a third-party payment system.

नेटफ्लिस्क के लिए कोई पासवर्ड साझाकरण नहीं

नेटफ्लिस्क ने अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में परीक्षण के बाद भारत, केन्या, इंडोनेशिया और क्रोशिया जैसे अन्य बाजारों में पासवर्ड साझा करना बंद कर दिया है।

कंपनी ने बताया कि 'हम यह ईमेल उन सदस्यों को भेजेंगे जो भारत में अपने घर के बाहर नेटफ्लिस्क साझा कर रहे हैं। एक नेटफ्लिस्क खाता एक परिवार द्वारा उपयोग के लिए है। उस घर में रहने वाला हर कोई नेटफ्लिस्क का उपयोग कर सकता है, चाहे वह कहीं भी हो–घर पर, चलते–फिरते, छुट्टी पर..और ट्रांसफर प्रोफाइल और एक्सेस और डिवाइस प्रबंधित करने जैसी नयी सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। हम मानते हैं कि हमारे सदस्यों के पास मनोरंजन के कई विकल्प हैं। यही कारण है कि हम विभिन्न प्रकार की नयी फिल्मों और टीवी शो में भारी निवेश करना जारी रखेंगे, इसलिए आपकी भाषा, स्वाद या मूड कुछ भी हो और आप जिसके साथ भी देख रहे हों, नेटफ्लिस्क पर देखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ संतोषजनक होता है।'

नेटफ्लिस्क की **2023** की दूसरी तिमाही की वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार इसने दूसरी तिमाही में **5.89** मिलियन ग्राहक प्राप्त किये हैं जिससे वैश्विक स्ट्रीमिंग भुगतान करने वाले ग्राहकों की कुल संख्या **238.39** मिलियन हो गयी है। क्यू **1** में नेटफ्लिस्क ने **1.75** मिलियन पेड सब्सक्राइबर जोड़े थे।

डिज्नी प्लस हॉटस्टार को अदालत से राहत

मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने गुगल प्ले स्टोर की नयी बिलिंग प्रणाली के खिलाफ याचिका दायर करने के बाद स्टार इंडिया की सहायक कंपनी नोवी डिजिटल एंटरटेनमेंट को अंतरिम राहत दी है। नोवी डिजिटल डिज्नी प्लस हॉटस्टार का मालिक है।

अदालत ने गुगल को ऐप स्टोर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार को हटाने से रोक दिया है।

नोवी डिजिटल को प्ले स्टोर डाउनलोड पर **4%** कमीशन देने के लिए कहा गया है। कंपनी ने अदालत को बताया कि नयी बिलिंग नीति के अनुसार ऐप डेवलपर्स को तीसरे पक्ष के भुगतान प्रणाली का विकल्प चुनने पर गुगल प्ले को **11%** शुल्क देना होगा।

GOVT MONITORING OTT CONTENT

I&B Minister Anurag Thakur met representatives of OTT platforms and addressed them on the aspects of content regulation, user experience, enhancing accessibility for the specially-abled, overall growth and innovation of the sector.

Thakur said OTT platforms have revolutionised the way we consume content, spurred new talent and showcased regional content on a global scale.

However, regarding regulation he said, "OTT players have a responsibility of ensuring that their platform does not propagate vulgarity and abuse camouflaged as 'creative expression'."

Thakur also said that India was a diverse country and the platforms must reflect the collective conscience of the country and provide a healthy viewing experience for people of all age groups.

"Platforms must also be sensitive to our cultural diversity as we unleash India's creative economy."

The representatives were from leading OTT platforms like Amazon Prime Video, Netflix, Viacom18 and Times Internet.

TRAI RELEASES CONSULTATION PAPER FOR OTT

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has released a consultation paper on the regulatory mechanism for Over-The-Top (OTT) communication services, and selective banning of OTT Services.

According to TRAI, the Department of Telecommunications (DoT) last year had written a letter and requested TRAI to reconsider its recommendations on the Regulatory Framework for OTT communication services and suggest a suitable regulatory mechanism for OTTs, including issues relating to 'selective banning of OTT services' as part of its recommendations. ■

TRAI

सत्यमेव जयते

Telecom Regulatory Authority of India

(IS/ISO 9001-2008 Certified Organisation)

ओटीटी सामग्री की निगरानी कर रही है सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ओटीटी प्लेटफॉर्मों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें सामग्री विनियमन, उपयोगकर्ता अनुभव, विशेष रूप से विकलांग लोगों तक पहुंच बढ़ाने, क्षेत्र के समग्र विकास और नयी खोजों के पहलुओं पर संबोधित किया।

श्री ठाकुर ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्मों ने हमारी सामग्री की उपभोग में क्रांति ला दी है, नयी प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया है, और क्षेत्रीय सामग्री को वैश्विकस्तर पर प्रदर्शित किया है। हालांकि विनिमय के संबंध में उन्होंने कहा कि 'ओटीटी खिलाड़ियों की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उनका मंच रचनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में अश्लीलता और दुर्व्यवहार का प्रचार न करे।

श्री ठाकुर ने यह भी कहा कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है और प्लेटफॉर्म को देश की सामूहिक चेतना को प्रतिबिंबित करना चाहिए और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए एक स्वस्थ्य देखने का अनुभव प्रदान करना चाहिए।

प्लेटफॉर्म को हमारी सांस्कृतिक विविधता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि हम भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को उजागर करते हैं।

इसमें अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, वायाकॉम 18 और टाइम्स इंटरनेट जैसे प्रमुख ओटीटी प्लेटफार्म के प्रतिनिधि शामिल थे।

ट्राई ने ओटीटी के लिए परामर्श पत्र जारी किया

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ओवर-द-टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं के लिए नियामक तंत्र और ओटीटी सेवाओं पर चुनिंदा प्रतिबंध लगाने के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया है।

ट्राई के अनुसार दूरसंचार विभाग (डॉट) ने पिछले साल एक पत्र लिखा था और ट्राई से अनुरोध किया था कि वह ओटीटी संचार सेवाओं के लिए नियामक ढ़ांचे पर अपनी सिफारिशों पर पुर्नविचार करे और ओटीटी के लिए एक उपयुक्त नियामक तंत्र का सुझाव दे, जिसमें, इसकी सिफारिशों में 'ओटीटी सेवाओं पर चयनात्मक प्रतिबंध' से संबंधित मुद्दे भी शामिल हों। ■